>

Title: Need to ban the import of garlic in the country.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, मुझे किसानों की उपज से संबंधित मामले पर आपने शून्य काल के दौरान बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश के किसानों को, उनकी खून-पसीने की कमायी को हमेशा ही नजरंदाज किया गया है। उनकी उपज का दाम कभी भी पूरा नहीं मिलता। जब से हमारे देश में कृषि उपज का आयात होने लगा है, खासकर उन उत्पाद का जिसका यहां काफी मात्रा में उत्पादन होता है, तब से हमारे किसान परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के लहसुन (गार्लिक) उत्पादक किसानों की समस्याओं के प्रति आकर्षित कराना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में, आज लहसुन जो हमारे दिनचर्या के भोजन व औषधि में तथा अन्यान्य पदार्थों में प्रयोग होता है, किसान उसका काफी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर, कुल्लू, मंडी, सोलन व शिमला में लहसुन का भरपूर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। आज यदि वर्ष 2007-08 के आंकड़ों को लिया जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 171.45 मिलियन हेक्टेअर में 923.23 मीट्रिक टन लहसुन की पैदावार होती है। जिसमें हिमाचल प्रदेश में 36.80 मीट्रिक टन पैदा किया जाता है। यहां पर कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का लहसुन उच्च कोटि का है तथा उसमें औषधीय गुण भी सबसे अच्छे हैं। यही नहीं पंजाब प्रांत को यदि छोड़ दिया जाए, जहां पर लहसुन का उत्पादन 15.64 टन प्रति हेक्टेअर होता है, वहीं हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। यहां पर इसका उत्पादन 13.78 टन प्रति हेक्टेअर है। पिछले कुछ दिनों से लहसुन का आयात चीन से हो रहा है, जिसके कारण हमारे किसान परेशान हैं, क्योंकि जिस कीमत पर चीन का लहसुन यहां बिक रहा है, उससे तो हमारे किसानों की उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो रही है।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि या तो लहसुन का आयात हमारे देश में पूरी तरह से रोक दिया जाए या उसके आयात पर इस प्रकार से टैक्स लगाया जाए ताकि हमारे उत्पादक किसानों को आयात के कारण नुकसान न हो।